

No.09(20)/2023-E.II(A)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
E.II(A) Branch

New Delhi, the 1st June, 2023

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Waiver of recovery of excess payment made to Government servants – General instructions for Ministries/Departments – reg.

The undersigned is directed to refer to DoP&T's instructions on the subject matter and to say that all the Ministries / Department are requested to adhere to the following instructions before referring the proposals involving waiver of recovery of excess payment to this Department:

- i. All proposals involving waiver of recovery of excess payment made to Government servants as covered under the guidelines issued by DoP&T should necessarily be forwarded to this Department, for consideration, by the Administrative Ministry / Department of the effected individual(s).
- ii. The Ministries/ Department are required to examine such proposal(s) at first instance in terms of Rule 17 of DFPRs and it may be certified that the loss does not disclose a defect in rules or procedures. If so, the same shall be brought to the notice of Department / Ministry who has the power to amend the order. Further, it has to be certified that there has not been any serious negligence on the part of any Government servant which may call for disciplinary action by a higher authority.
- iii. The matter should be referred to this Department in a self contained note duly explaining the case(s) in chronological order. The cases which are fairly and squarely covered under any one of the five situations as mentioned in DoP&T's OM dated 02.03.2016 should be recommended by the Financial Advisor and approved by the Administrative Secretary.

iv. Cases which are sub-judice should be forwarded to this Department along with the final order of the Court. The grounds for implementing / not challenging the order may be suitably justified. As such, any legal advice, if sought, may also be provided.

v. The offices / divisions where such anomalies have occurred shall indicate the steps / measures adopted by them to contain the recurrence of such lapse(s) in future. If any inquiry has been made to fix the responsibility, the final report as well as action taken by the Ministry may be furnished.

vi. This Department has observed that the wrongful pay fixation goes unnoticed for a long period of time by the concerned authorities. Ministry may furnish suitable justification as to how such cases were not noticed during regular review, internal audit etc.

2. This has the approval of the Competent Authority.



(Chandra Prakash Kushwaha)
Under Secretary to the Govt. of India

To

1. All Ministries/Department of Government of India.
2. Financial Advisor of all Ministries/Departments of Government of India.

सं.09(20)/2023-ई.॥(ए)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

ई.॥(ए) शाखा

नई दिल्ली, 01 जून, 2023

कार्यालय जापन

विषय: सरकारी सेवकों को किए गए अधिक भुगतान की वसूली का अधित्याग-मंत्रालयों/विभागों के लिए सामान्य अनुदेशों के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त मामले पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुदेशों का संदर्भ लेने और यह कहने का निदेश हुआ है कि सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अधिक भुगतान की वसूली के अधित्याग से संबंधित प्रस्तावों को इस विभाग को भेजने से पहले निम्नलिखित अनुदेशों का अनुसरण करें:

- i कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत यथा-संरक्षित सरकारी सेवकों को किए गए अधिक भुगतान की वसूली के अधित्याग से संबंधित समस्त प्रस्तावों को प्रभावित व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा अनिवार्य रूप से इस विभाग को विचारार्थ भेजा जाना चाहिए।
- ii मंत्रालयों/विभागों द्वारा ऐसे प्रस्ताव (प्रस्तावों) की प्रथमतः डीएफपीआरएस के नियम-17 के अनुसार जांच की जानी अपेक्षित है तथा यह प्रमाणित किया जाए की क्षति से नियमों अथवा प्रक्रियाओं में कोई दोष प्रकट नहीं होता है। यदि ऐसा है तो, उसे उस विभाग/मंत्रालय के ध्यान में लाया जाएगा, जिसके पास उक्त आदेश को संशोधित करने की शक्ति हो। इसके अतिरिक्त, यह प्रमाणित किया जाना है कि किसी सरकारी सेवक की ओर से ऐसी कोई गंभीर लापरवाही नहीं हुई है, जिसके लिए किसी उच्चतर प्राधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता हो।
- iii कालक्रम के अनुसार प्रकरण (प्रकरणों) की विधिवत् व्याख्या करते हुए एक स्वतः स्पष्ट नोट में मामला इस मंत्रालय को भेजा जाना चाहिए। ऐसे प्रकरण, जो दिनांक 02.03.2016 के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय जापन में किए गए उल्लेख के अनुसार पांच स्थितियों में से किसी एक के अधीन निष्पक्ष और निष्कपट रूप से संरक्षित हों, उन्हें वित्तीय सलाहकार द्वारा संस्तुत किया जाए तथा प्रशासनिक सचिव द्वारा अनुमोदित किया जाए।

क्रमशः पृष्ठ-2/-पर

- iv ऐसे मामले जो निर्णयाधीन हों, न्यायालय के अंतिम आदेश के साथ इस विभाग को अग्रेषित किए जाने चाहिए। उन कारणों, जिनके आधार पर आदेश को कार्यान्वित किया जाना हो/चुनौती न दी जानी हो, का समुचित रूप से औचित्य निर्धारित किया जाए। इस प्रकार से, यदि कोई विधिक राय ली गई हो, उसे भी मुहैया कराया जाए।
- v ऐसे कार्यालय/प्रभाग, जहां ऐसी विसंगतियाँ पैदा हुई हैं, भविष्य में ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों/उपायों की जानकारी देंगे। जवाबदेही तय करने के लिए यदि कोई जांच पड़ताल की गई है, तो मंत्रालय द्वारा अंतिम रिपोर्ट के साथ-साथ की गई कार्रवाई प्रस्तुत की जाए।
- vi इस विभाग ने पाया है कि दोषपूर्ण वेतन निर्धारण के मामलों में संबंधित प्राधिकारी लंबे समय तक बेखबर रहते हैं। मंत्रालय, इस संबंध में समुचित औचित्य प्रस्तुत करें कि कैसे इस प्रकार के मामले नियमित पुनरीक्षण, आंतरिक लेखा परीक्षा आदि के दौरान नोटिस नहीं किए गए।

2. इसे सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।



(चन्द्र प्रकाश कुशवाहा)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के वित्तीय सलाहकार।